



कॉर्पोरेट शासन प्रणाली

1.1 आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड ने डीपीई द्वारा कारपोरेट शासन प्रणाली के मार्गदर्शकों को ईमानदारी से पालन करती है तथा सभी स्टेडक होल्डर के अधिकार को श्रेष्ठता देती है। पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्वक मान्यताओं द्वारा कंपनी का नीति प्रतिबिम्बित होती है। अपने वित्तीय एवं निष्पाकदन के साथ शासन प्रणाली के संबंध में समय पर सही सूचना देना, कंपनी अपना निहित दायित्व समझती है।

1.2 आईआरईएल ने कारपोरेट शासन पर डीपीई के मार्गदर्शन के अनुसार अपने बोर्ड का श्रेणी एवं संयोजन बनाए रखी है।

1.3 आईआरईएल का बोर्ड, सभी सांविधिक समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति एवं सीएसआर समिति के साथ संघटित/संस्थापित किया गया।

1.4 बोर्ड तथा उसके संविधि समितियों का बैठक डीपीई मार्गदर्शन एवं संविधि के अनुसार बुलाया, आयोजित एवं संचालित किया जाएगा।

2.0 बोर्ड द्वारा नियुक्त संविधि समितियों के संदर्भ की शर्तें

2.1 लेखा-परीक्षा समिति की मुख्यतः शर्तें

- (i) बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा
- (ii) आंतरिक लेखा-परीक्षा, सांविधिक लेखा-परीक्षा एवं सरकारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा
- (iii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं आंतरिक लेखा-परीक्षकों, प्रबन्धन के साथ समीक्षा।
- (iv) वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लागू लेखा-विधि मानक एवं अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- (v) अर्थपूर्ण लेखा-विधि नीतियाँ एवं परिवर्तन यदि कुछ है तो समीक्षा करना।

- (vi) लेखा-परीक्षा योग्यताएं यदि कुछ हैं तो समीक्षा ।
- (vii) लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति सिफारिश ।
- (viii) सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं लागत लेखा परीक्षकों के लेखा-परीक्षा शुल्क को नियत करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना ।
- (ix) कर लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक को नियतन एवं नियुक्तक करना ।
- (x) सांविधिक रूप से निषेधित न होने पर अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान अनुमोदित करना ।
- (xi) लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट एवं कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा ।
- (xii) अर्थ-पूर्ण निष्कर्ष तथा उसपर अनुवर्ती, आदि कुछ हैं तो आंतरिक लेखा-परीक्षकों के साथ चर्चा करना ।

2.2 “नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति” के शर्तों का संदर्भ में वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल पर निर्णय लेना, संबंधित नीति के अनुसार अधिकारियों एवं असंघटित पर्यवेक्षकों को उसके वितरण के लिए कुछ हैं तो निर्धारित सीमाओं के अंदर तथा ऐसे मामलों में बोर्ड समय समय पर पारिश्रमिक समिति को जांच एवं अनुमोदन के लिए भेजना है ।

2.3 “सीएसआर समिति” की भूमिका

- (i) बोर्ड को कंपनी द्वारा लिये जानेवाले कार्यकलापों के साथ सीएसआर नीति को सूत्रबद्ध एवं सिफारिश करना ।
- (ii) बोर्ड को नीति में निर्धारित कार्यकलापों के लिए समय समय पर होनेवाली खर्च की राशि को सिफारिश करना ।
- (iii) सीएसआर नीति को मानीटर करना ।